

मुख्यमंत्री ने गुढ़ में किया भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने विकास-धरोहर को नई ऊँचाई पर पहुंचाने का लिया संकल्प

रीवा, 31 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और आधुनिक विकास को नई दिशा दी जा रही है। उन्होंने भैरवनाथ मंदिर का विधिवत लोकार्पण करते हुए इसे आस्था और प्राचीन विरासत का जीवंत प्रमाण बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आस्था के केंद्रों को भव्य रूप दे रही है, साथ ही लाइली बहनों को आर्थिक मजबूती और किसानों की समृद्धि के साथ 'इंडस्ट्रियल क्लस्टर' के माध्यम से युवाओं के



लिए रोजगार के नए द्वार खोल रही हैं। उन्होंने सनातन संस्कृति के वैभव

को रेखांकित करते हुए अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ के

पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख किया। प्रदेश

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विध्य का पूरे देश में नाम हो रहा है: राजेन्द्र शुक्ल

समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि गुढ़ क्षेत्र के लिए भैरवनाथ और कटहरनाथ मंदिर आस्था के केंद्र हैं। गुढ़ में सोलर प्लांट स्थापना के बाद उसके सीएसआर मद से इन दोनों मंदिरों में विकास के कार्य किए गए हैं। गुढ़ में तीन सीएकड क्षेत्र में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्वलेस से विध्य में तेजी से निवेश बढ़ा है।

मंत्रालय के गलियारे से



कन्हैया लोधी

क्या कांग्रेस का कोई विकेट गिरेगा

राजनीतिक गलियारों में अंदरखाने ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या कांग्रेस का कोई विकेट गिरेगा। दरअसल पिछले दिनों एक यात्रा के दौरान सरकार को नजर एक विधायक पर पड़ी। सरकार ने भी पूरी उदारता दिखाते हुए सिर पर हाथ रख

दिया। विधायक ने अपना मांग पत्र भी दिया। सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया। तब से कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है कि क्या माननीय वक्त आने पर पाता बदल लेंगे। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।

दो नेताओं का पॉवर गेम

मप में आने वाले दिनों में कभी बेहद कठोर रहे दो नेताओं का पॉवर गेम देखने मिलेगा। दोनों ही नेता इन दिनों अपने-अपने आयोजन के लिए बेहद सक्रिय हैं और आयोजन को भूतो न भविष्यति बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इन दोनों ही नेताओं के बारे में ये भी संयोग ही है कि ये पिछले कार्यकाल तक बेहद पॉवरफुल थे लेकिन अभी राजनीतिक वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दोनों के ही आयोजन में धर्म जुड़ा हुआ है। अब देखा ये है कि उनके इस सद्कार्य का भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।

ये जुबां है कि सुधरती नहीं

वैसे अपना-शनाप बयानबाजी के लिए मप के एक मंत्री पहले ही बदनम हैं, उनकी बयानबाजी ने ही उन्हें ऐसे फंसाया कि वे अब तक उबर नहीं पाए हैं और कभी भी लेने के देने पड़ सकते हैं। उनकी कतार में एक और नेताजी जुड़ गए हैं। ये नेताजी तो वैसे बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन लगता है कि वे लगातार ट्रेक से उतरते जा रहे हैं, नतीजा वे जब-तब कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। पिछले दिनों कमीशनरों को लेकर ऐसी बातें बोल दीं, जिस कारण वे कटघरे में आ गए, उससे पहले वे सबसे स्वच्छ शहर के हादसे को लेकर भी ऐसा बोल चुके हैं, यानी जुबां है कि अब सुधरती नहीं।

चर्चा में साहब का तबादला

पिछले दिनों आईपीएस अफसरों की तबादले की सूची जारी हुई। इसमें एक अफसर का तबादला बेहद चर्चा में बना रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे पहले हटाया गया था उसे ही बाद में विभाग की कमान सौंप दी गई। अब इसके बाद चर्चा चल पड़ी है कि क्या विभाग में पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है, ये इसलिए कि साहब को शाम, दाम, दंड और भेद में बेहद माहिर माना जाता है। यानी चोतरफा कृपा बरसाने में ये सिद्धहस्त हैं।

9.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क

भोपाल, 31 जनवरी. प्रवर्तन निदेशालय के भोपाल जौनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मिश्र और उनकी पत्नी अलका मिश्र की लगभग 9.79 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई है। ईडी ने जांच लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि जांच अवधि के दौरान डॉ. मिश्र की वैध आय लगभग 60 लाख रुपये थी, जबकि संपत्तियों और खर्चों की कुल राशि करीब 2.98 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार उनके पास लगभग 2.38 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति होने का खुलासा हुआ। ईडी के अनुसार, डॉ. मिश्र ने चल और अचल संपत्तियां अपने नाम के साथ-साथ पत्नी और ए.एन. मिश्र एचएचएफ के नाम पर भी अर्जित कीं, जिससे अवैध धन को छिपाने का प्रयास किया गया।

महाकालेश्वर में 6 से 15 फरवरी शिव नवरात्रि महा उत्सव

10 दिन होंगे विशेष श्रृंगार

उज्जैन, 31 जनवरी. श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व परंपरागत श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष शिव नवरात्रि महा उत्सव 6 फरवरी से 15 फरवरी तक कुल 10 दिनों तक आयोजित किया जाएगा।

पर्व को सुव्यवस्थित और भव्य रूप से संपन्न कराने के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। तैयारियों के तहत मंदिर के मुख्य शिखर की धुलाई, परिसर की रंग-रोगन, कोटिदार्थ कुंड की सफाई तथा मंदिर परिसर और



आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। शिव नवरात्रि के दौरान भगवान महाकाल का प्रतिदिन विशेष पूजन-अर्चन और भिन्न-भिन्न स्वरूपों में श्रृंगार किया जाएगा। उत्सव का शुरुआत 6 फरवरी को भांग-चंदन श्रृंगार से होगा।

प्रधान आरक्षक जांच में आरोप सिद्ध होने पर सेवा से पृथक

शिवपुरी. पुलिस लाइन में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को गंभीर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छा पूर्ण व्यवहार के कारण तथा जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद सेवा से पृथक कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए सेवा से पृथक किए गए प्रधान आरक्षक का नाम शिवराज भगत बताया है। प्रधान आरक्षक पुलिस सेवा के दौरान 10 बार से अधिक लंबी लंबी अवधि के लिए बिना सूचना के अनुपस्थित रहा। पुलिस सेवा के योग्य नहीं पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा प्रधान आरक्षक को सेवा से पृथक कर दिया गया है।

अंत्योदय में 35 किलो निःशुल्क राशन

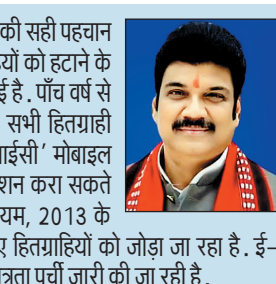
5.37 करोड़ आबादी को प्रतिमाह मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है

भोपाल, 31 जनवरी. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 5.37 करोड़ आबादी को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

अंत्योदय अन्न योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को 35 किलोग्राम तथा प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। सभी पात्रता पर्चीधारी परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से नियमित रूप से राशन मिल रहा

हे. मंत्री ने कहा कि 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के तहत पात्र परिवार का कोई भी सदस्य प्रदेश या देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन, ओटीपी अथवा नामनी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

प्रदेश में 15 लाख से अधिक पात्र परिवार पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ लेकर अपनी सुविधा अनुसार अन्य दुकानों से राशन प्राप्त कर रहे हैं। पूरे माह राशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।



भारत सरकार द्वारा पात्र परिवारों की सही पहचान और अपात्र अथवा दोहरे हितग्राहियों को हटाने के लिए ई-केवाईसी अभियान की गई है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर सभी हितग्राही पीओएस मशीन या 'मेरा ई-केवाईसी' मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 29 पात्रता श्रेणियों में नए हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है। ई-केवाईसी के तीन दिनों के भीतर पात्रता पर्ची जारी की जा रही है।

प्रदेश में बढेगी टंड, आंधी-बारिश का अलर्ट

भोपाल, 31 जनवरी. मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में मौसम ने एक बार फिर कर्वट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।

ग्वालियर, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित करीब 20 जिलों में हल्के से लेकर घने कोहरे का असर देखा गया। सतना में घना कोहरा छाया रहा, जबकि राजगढ़ जिले में प्रदेश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे के इस दौर के बाद प्रदेश में आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। 1 से 3 फरवरी के बीच कई जिलों में बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की



रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसका सबसे अधिक असर ग्वालियर, चंबल, सागर और उज्जैन संभाग में देखने को मिलेगा। बारिश के बाद एक बार फिर टंड के असर में बढ़ोतरी होने

की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। रीवा, सीधी, नौगांव (छतरपुर) और दमोह जिलों में

दूसरी ओर रीवा और सागर संभाग में तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ उत्तर अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय है, जिसका प्रभाव मध्य भारत के मौसम पर पड़ रहा है। इसके साथ ही उत्तर भारत में तेज गति से बढ़ रही उष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं भी मौसम परिवर्तन का कारण बन रही हैं।

शीतल दिन की स्थिति बनी रही। अधिकतम तापमान में भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में 2.8 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं उज्जैन और शाहडोल संभाग में तापमान सामान्य से 4.7 से 4.9 डिग्री तक अधिक रहा।

हत्या कर पेटी में छिपाया शव

13 साल का बच्चा था आतिफ अली

नव भारत न्यूज इंदौर. शहर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें 13 साल के एक बच्चे आतिफ अली की बेरहमी से छत पर हत्या कर फ्लैट के एक कमरे में छिपा दिया। फ्लैट में रखी एक पलंग पेटी को आरोपी रेहान ने शव को रख कर उसे कब्र की तरह ढांक दिया। फिर उस पर अपनी बीमार दादी को सुला दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा रिजवान फरार है। पूरी घटना का खुलासा जांच के दौरान सामने आया फ्लैट के आधार पर हुआ है। आरोपी आपस में दोस्त ही हैं। थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि



बच्चे आतिफ की हत्या बेहद निर्ममता से की गई। पहले नायलॉन की रस्सी से उसका गला चोंटा गया, इसके बाद चेहरे पर ईंट से हमला किया। हत्या के बाद आरोपी घबरा गए और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को रेहान के घर पलंग की पेटी में डाल दिया, वारदात शनिवार को बच्चे के घर से करीब 30 मीटर दूर स्थित एक छह मंजिला इमारत की छत पर की गई। इसके बाद शव को उसी इमारत के चौथी मंजिल स्थित एक फ्लैट में ले जाकर छिपाया।

रामजी योजना से गांधी के सपने साकार

बैतूल/भोपाल, 31 जनवरी. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने शनिवार को बैतूल स्थित भाजपा जिला कार्यालय में वीबी जी-रामजी योजना को लेकर आयोजित जिला कार्यशाला को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर कांग्रेस समाज में भ्रम और झूठ फैला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इसके माध्यम से महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं। श्री खण्डेलवाल ने कहा कि पहले इस योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जिसे



बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान नए कानून में किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में कई राष्ट्रीय योजनाओं के नाम बदले, लेकिन कभी उनके मूल उद्देश्य को सशक्त करने का कार्य नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था,

जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 के बाद जनआंदोलन का रूप दिया। आज स्वच्छता देशव्यापी अभियान बन चुकी है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर वीबी जी-रामजी योजना की वास्तविक जानकारी जन-जन तक पहुंचाएं और मजदूरों के हितों को समजवूत करने वाले प्रावधानों को मजबूत करें।

सूबेदारगंज-एलटीटी के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन

भोपाल. यात्रियों की सुविधा और यात्रा मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 04115/04116 सूबेदारगंज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सूबेदारगंज के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

यह स्पेशल ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी। ट्रेन संख्या 04115 (सूबेदारगंज-एलटीटी) प्रत्येक गुरुवार दिनांक 05 मार्च 2026 से 26 दिसंबर 2030 तक सूबेदारगंज से दोपहर 12:10 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सतना 00:15, मैहर 00:48, कटनी 01:55, जबलपुर 03:20, नरसिंहपुर 04:33, पिपरिया

05:38, इटारसी 07:40 पहुंचकर शुकुवार रात 20:50 बजे एलटीटी पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04116 प्रत्येक शुकुवार दिनांक 06 मार्च 2026 से 27 दिसंबर 2030 तक एलटीटी से रात 22:50 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन इटारसी 11:15, पिपरिया 12:24, नरसिंहपुर 13:30, जबलपुर 15:30, कटनी 16:50, मैहर 17:43, सतना 18:50 पहुंचकर तीसरे दिन रविवार सुबह 07:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 06 एसी-3 टियर, 04 एसी-3 टियर इकॉनॉमी, 06 स्लीपर क्लास, 04 जनरल सेकंड और 01 जनरेटरकार, 01 एसएलआरडी सहित 22 कोच रहेंगे।

स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियां उजागर

विशेष संवाददाता

भोपाल/विदिशा. 31 जनवरी. विदिशा जिले में एक गंभवती महिला को कड़ाके की ठंड में तिरपाल की ओट और टॉर्च की रोशनी में सड़क किनारे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यह घटना कोई दुर्भाग्यपूर्ण अपवाद नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी सच्चाई को उजागर करने वाला गंभीर आरोप है। जानकारी के अनुसार, महिला को समय पर न तो 108 एम्बुलेंस सेवा मिली और न ही जन्मी एक्सप्रेस, जबकि आपातकालीन सेवाएं पूरी रात निष्क्रिय रहीं। कागजों में अस्पताल और डॉक्टरों की मौजूदगी के बावजूद, जमीनी स्तर



पर पूरी व्यवस्था नदारद देखी। यह घटना राज्य सरकार के उन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिनमें 'सुलभ, सशक्त और संवेदनशील' स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही जाती है। यदि मध्य प्रदेश को 'स्वास्थ्य मॉडल' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो एक महिला को खुले आसमान के नीचे प्रसव क्यों करना पड़ा? सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं पर हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च करने और 108 एम्बुलेंस के चौबीसों घंटे संचालन का दावा करती हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविकता इन दावों की पोल खोलती है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण धोलपुरे ने इस मामले में स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की है। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं, सीएमएचओ और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से यह भी पूछा कि बजट खर्च होने के बावजूद लाभ आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। टॉर्च की रोशनी में जन्मा यह बच्चा, उन्होंने कहा, सरकार के विकास और संवेदनशील शासन के दावों के खिलाफ एक जीवित चार्जशीट है।

बजट आज आम बजट में मध्यप्रदेश को मिल सकती है पैकेज के तहत अतिरिक्त राशि

सिंहस्थ के लिए स्पेशल पैकेज पर टिकीं मप्र की उम्मीदें

कन्हैया लोधी भोपाल, 31 जनवरी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये आम बजट पेश करेंगी। केंद्र के बजट से पहले मप्र सरकार ने भी उम्मीदों से भरा ड्राफ्ट पहले ही केंद्र सरकार को सौंप दिया था, जिसमें मप्र के लिये आम बजट में विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है।

सर्वसे बड़ी बात यह कि मप्र ने सिंहस्थ 2028 के लिये केंद्र सरकार से 20 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। हाल के वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मप्र ने एक साथ इतनी बड़ी राशि की मांग की हो, इस



पैकेज की मांग पर मप्र सरकार की पूरी उम्मीदें टिकी हैं। दरअसल मप्र सरकार पहले ही उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों युद्ध स्तर पर शुरू कर चुकी है। प्रदेश में डॉ. मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से ही उज्जैन में सिंहस्थ के कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर

रखा गया है, जिसके चलते यहां लगभग 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक के काम या तो शुरू हो गये हैं, या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में हैं। ये ज्यादातर निर्माण अधोसंरचना से जुड़े हैं। इन कामों में सड़क निर्माण, घाट निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, यात्रियों के ठहरने के स्थलों

का विकास करने के साथ ही श्रद्धालुओं के बेहतर इलाज के लिये यहां चिकित्सालय सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। क्षिप्रा में क्षिप्रा के पानी से ही सिंहस्थ स्नान कराने की तैयारी भी की गई है, जिसका काम पहले से ही तेज गति से चल रहा है।

इस परियोजना पर भी बड़ी राशि खर्च की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार के लिये अपने स्त्रोतों से पैैसे का इंतजाम करना आसान नहीं है। लिहाजा अब केंद्र से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उसे स्पेशल पैकेज मिल जाए। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21

जल जीवन मिशन के 8 हजार करोड़ अटके

केंद्र सरकार के पास जल जीवन मिशन के लगभग 8 हजार करोड़ रुपए अब तक अटके हुए हैं, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। दरअसल मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 फीसदी की भागीदारी है। राज्य सरकार का तर्क है कि पिछले वित्तीय वर्ष और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिये मिशन के तहत कामों के लिये केंद्र से राशि नहीं मिली है, ऐसे में राज्य सरकार अपने ही खर्च से मिशन का काम करा रही है। जिस कारण मप्र सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ गया है। राज्य सरकार ने केंद्र को जो ड्राफ्ट सौंपा है, उसके मुताबिक वर्ष 2024-25 के लिये 4370 करोड़ रुपए और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिये 3750 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है।

की अवधि में राज्यों में अधोसंरचना से जुड़े कामों को बढ़ावा देने के लिये विशेष पूंजीगत सहायता योजना शुरू की थी। मप्र सरकार का तर्क है कि उसने इस योजना का पूरा फायदा उठाया है और उसके लिये जो लक्ष्य तय किये गये थे, वह उसने हासिल कर लिया है, इसके लिए उसे केंद्र से अतिरिक्त राशि भी मिली।